लोकसभा और उसके अधिकार

लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जिसमें अपने प्रतिनिधि का चयन जनता सीधे करती है। संविधान के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है जिसमें 530 सांसद राज्यों और 20 केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही नहीं अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो-इंडियन समुदाय को उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो है तो वह इस समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया इस तरह बनाई गई है कि हर राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और वहां की जनसंख्या के बीच अनुपात जहां तक संभव हो एक समान ही रहे।

कार्यकाल : लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर पांच साल के लिए होता है लेकिन राष्ट्रपति को इसे समय से पहले भंग करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने की स्थिति में संसद द्वारा ही पारित अधिनियम के तहत सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार में यह अवधि

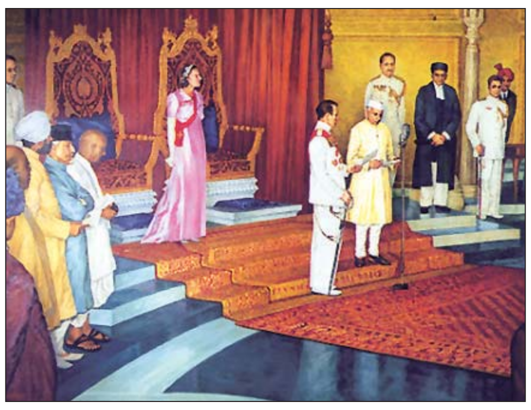

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब ब्रिटिश शासन से सत्ता अपने हाथ में ली तो नजारा कुछ ऐसा था।

एक साल से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती और किसी भी स्थिति में आपातकाल खत्म होने की घोषित अवधि से छह माह आगे नहीं हो सकती है।

अधिकार : लोकसभा प्रतिनिधि का चयन सीधे जनता के वयस्क मताधिकार से होता है इसलिए इसे लोकप्रिय चैंबर भी कहते हैं। यही नहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा के मुकाबले इसके अधिकार भी कुछ ज्यादा है। निर्वाचित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और पारित होने की स्थिति में सरकार गिरा देना सिर्फ लोकसभा सदस्यों के हाथ में होता है। राज्यसभा सदस्य ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करने का अधिकार है जिसे राष्ट्रपति आम तौर पर मंजूर कर लेते हैं। वित्त विधेयकों को छोड़कर विधायी मामलों में दोनों सदनों की शक्तियां लगभग बराबर होती हैं। वित्त विधेयकों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है और वहां पारित होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है। अगर राज्यसभा ने उसे 14 दिन के अंदर वापस न भेजा तो उसे पारित मान लिया जाता है। वित्त विधेयकों में राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। यदि राज्यसभा ने कोई सिफारिश की है तो उसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा का विशेषाधिकार है। वित्त को छोड़कर अन्य विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और वहां से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए दूसरे सदन को भेजे जाते हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद ही कोई कानून पारित हो पाता है।

देश में जल्द ही लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है तो हमने सोचा कि क्यों न आपको अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में कुछ ऐसी सूचनाएं मुहैया कराएं जिससे यह समझने में आसानी हो कि हमारे सांसद जी ने अपनी जिम्मेदारियां कुशलता से निभाई भी या नहीं। मसलन, उन्होंने सांसद क्षेत्रीय विकास निधि के तहत मिलने वाली राशि से कितना विकास कार्य कराया और किन मुद्दों को सदन में उठाया। ये सारी जानकारियां सतर्क नागरिक संगठन ने सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) का इस्तेमाल करके और कुछ सरकारी वेबसाइटों के जरिये जुटाई है।

हिन्दुस्तान

सतर्क नागरिक संगठन

राहुल गांधी (कांग्रेस), अमेठी (उत्तर प्रदेश)

लोकसभा में प्रदर्शन (2007)

उपस्थिति	तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न	बिल पेश किए गए	कार्यवाही में हिस्सेदारी (प्रश्नों को छोड़कर)
33/66	0	0	0	0

मुद्दे	प्रश्नों की सं.	हिस्सेदारी
आंतरिक सुरक्षा	-	-
रक्षा	-	-
विदेश नीति	-	-
सामाजिक कल्याण	-	-
महिला एवं बाल कल्याण	-	-
आर्थिक मुद्दे	-	-
बजट	-	-
इंफ्रास्ट्रक्चर	-	-
पर्यावरण	-	-
जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता	-	-
लोकतांत्रिक मुद्दे	-	-
अन्य	-	-
कुल	0	0

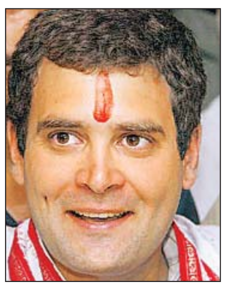

19 जून 1970 को नई दिल्ली में जन्मे राहुल गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं है. कांग्रेस महासचिव के साथ-साथ यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के प्रभारी भी हैं. ट्रीनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से एमफिल किया. राजनीति में आने से पूर्व लंदन में स्ट्रेट्जी कंसल्टेन्सी फार्म मॉनिटर ग्रुप से जुड़े और मुंबई में इंजीनियरिंग फर्म से भी जुड़े रहे. प्राथमिक शिक्षा को बहुआयामी बनाने का सपना. अमेठी के लोग भावी प्रधानमंत्री मानते हैं. दौरे के समय सुरक्षा घेरा तोड़ झलक पाने को उमड़ता है रैला. दलित परिवारों के यहां रात बिता उनकी माली हालत से रू-ब-रू हुए। अमेठी में संगठन की बूथ स्तर तक मजबूती के लिए बेजोड़ नेटवर्क बनाया. इससे प्रेरणा लेकर सुलतानपुर में भी संगठन का पुनर्गठन जारी.

सांसद निधि खर्च का ब्योरा (2004-08)

मद	रुपये (लाख में)
सड़क, गली और फुटपाथ	232.3
नाली	0.0
बिजली	6.4
पार्क	0.0
पानी	89.2
स्कूल-कॉलेज	47.8
बारात घर	18.4
-	-
-	-
-	-
कुल	394.1

सांसद निधि से हर वर्ष दो करोड़ तक विकास कार्य संभव

संसदीय समिति में सदस्यता (2004-08)

10 अक्तूबर 2006 से 4 अगस्त 2008 तक मानव संसाधन विकास मामलों की संसदीय समिति के सदस्य रहे. 5 अगस्त 2004 से 9 अक्तूबर 2006 तक गृह मामलों की समिति में सदस्य.

संसदीय समिति में प्रदर्शन (2007-08)

कमेटी का नाम	सदस्य की स्थिति	कब से	कब तक	हाजिरी
मानव संसाधन एवं विकास	सदस्य	05.8.07	04.8.08	2/13

नवजोत सिंह सिद्धू (भाजपा) अमृतसर (पंजाब)

लोकसभा में प्रदर्शन (2007)

उपस्थिति	तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न	बिल पेश किए गए	कार्यवाही में हिस्सेदारी (प्रश्नों को छोड़कर)
16/59	0	26	0	0

मुद्दे	प्रश्नों की सं.	हिस्सेदारी
आंतरिक सुरक्षा	3	-
रक्षा	-	-
विदेश नीति	-	-
सामाजिक कल्याण	2	-
महिला एवं बाल कल्याण	-	-
आर्थिक मुद्दे	10	-
बजट	-	-
इंफ्रास्ट्रक्चर	6	-
पर्यावरण	2	-
जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता	-	-
लोकतांत्रिक मुद्दे	3	-
अन्य	-	-
कुल	26	0

पंजाब के पटियाला जिले में 20 अक्तूबर, 1963 को जन्मे नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट की दुनिया से संन्यास के बाद राजनीति, टीवी व फिल्म क्षेत्र में खासी धाक जमाई। 2004 में भाजपा में शामिल. इसी साल दिसंबर में अमृतसर से लोस चुनाव जीता. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिसंबर 2006 में सिद्धू को एक पुराने मामले में दोषी ठहरा तीन साल की सजा सुनाई थी। 1988 में एक वाहनों की पार्किंग को लेकर झगड़े में सिद्धू की पिटाई से 65 वर्षीय गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। सजा के बाद सिद्धू का इस्तीफा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक के बाद अमृतसर से उपचुनाव लड़ फिर सांसद बने. अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे पंजाब में छवि काफी अच्छी. पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं.

सांसद निधि खर्च का ब्योरा (2004-08)

मद	रुपये (लाख में)
सड़क, गली, फुटपाथ	387.1
नाली	26.0
बिजली	14.9
पार्क, फाउंटेन	12.8
सीवर, टॉयलेट	35.4
कम्युनिटी सेंटर	158.7
स्कूल	121.2
श्मशान	73.0
अस्पताल उपकरण खरीद	50.2
जिम निर्माण	28.4
अन्य	80.3
कुल	988.0

सांसद निधि से हर वर्ष दो करोड़ तक विकास कार्य संभव

संसदीय समिति में सदस्यता (2004-08)

4.12.06 को लोकसभा से इस्तीफा दे देने वाले सिद्धू 27 फरवरी 07 के उपचुनाव में फिर निर्वाचित. 7 मार्च 2007 को शपथ ली. अपने पूर्व के कार्यकाल के दौरान 5.8.04. से 4.12.07 तक शहरी विकास समिति के सदस्य रहे.

संसदीय समिति में प्रदर्शन (2007-08)

कमेटी का नाम	सदस्य की स्थिति	कब से	कब तक	हाजिरी

उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक वर्ष 2007 में नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी संसदीय समिति के सदस्य नहीं रहे.

हरीश नागपाल (निर्दलीय) अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

लोकसभा में प्रदर्शन (2007)

उपस्थिति	तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न	बिल पेश किए गए	कार्यवाही में हिस्सेदारी (प्रश्नों को छोड़कर)
4/66	0	0	0	0

मुद्दे	प्रश्नों की सं.	हिस्सेदारी
आंतरिक सुरक्षा	-	-
रक्षा	-	-
विदेश नीति	-	-
सामाजिक कल्याण	-	-
महिला एवं बाल कल्याण	-	-
आर्थिक मुद्दे	-	-
बजट	-	-
इंफ्रास्ट्रक्चर	-	-
पर्यावरण	-	-
जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता	-	-
लोकतांत्रिक मुद्दे	-	-
अन्य	-	-
कुल	0	0

नागपाल का जन्म तीन अगस्त,1964 को हुआ. अमरोहा के ही रहने वाले हैं और बड़े शराब व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गाजियाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ा, पर जीते नहीं. पत्नी अंजुला ने गाजियाबाद से सपा के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा पर दूसरे स्थान पर रहीं. भाई देवेन्द्र नागपाल मुरादाबाद की हसनपुर वि.स. सीट से निर्दलीय विधायक रहे हैं. हरीश नागपाल एटमी करार मुद्दे पर यूपीए के खिलाफ वोट करने के लिए चर्चित रहे. बदले में भाजपा ने अमरोहा से लोकसभा टिकट का वादा किया था. अमरोहा के एक होटल में लेट नाइट पार्टी के दौरान मुंबई की बार डांसर्स को बुलाने के लिए भी हरीश नागपाल चर्चाओं में रहे.

सांसद निधि खर्च का ब्योरा (2004-08)

मद	रुपये (लाख में)
सड़क, गली और फुटपाथ	582.3
नाली	59.6
बिजली	15.6
पार्क	0.0
पानी	10.3
सीवर	0.0
स्कूल	22.8
कम्युनिटी सेंटर	5.4
-	-
अन्य	3.2
कुल	699.1

सांसद निधि से हर वर्ष दो करोड़ तक विकास कार्य संभव

संसदीय समिति में सदस्यता (2004-08)

नागपाल 10 अगस्त 2004 से 4 अगस्त 2006 तक खाद्य, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मामले की समिति और 5 अगस्त 2006 से 4 अगस्त 2008 तक सूचना प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य रहे.

संसदीय समिति में प्रदर्शन (2007-08)

कमेटी का नाम	सदस्य की स्थिति	कब से	कब तक	हाजिरी
सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य	05.8.07	04.8.08	0/26

ये सूचनाएं लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के पूर्व की स्थिति के मुताबिक हैं। **तारांकित प्रश्न :** ऐसे सवाल जिनका सांसद सदन में मौखिक जवाब चाहते हैं। **अतारांकित प्रश्न :** यानी वे सवाल जिनका सांसद लिखित जवाब मांगते हैं।

मंदिर मसले पर भाजपा और एनडीए में घमासान

प्रदीप सौरभ नई दिल्ली

- जदयू प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि राममंदिर धारा-370 का प्रवेश एनडीए में वर्जित है
- अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि राममंदिर भाजपा एजेंडा हो सकता है एनडीए का नहीं

भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर को लेकर नागपुर से उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के अंदर इस मसले को लेकर खींचतान तो बनी ही हुई है। एनडीए के घटक दल भी इस मसले पर अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। जेडीयू तो इस मसले पर अंदरखाने काफी नाराज है। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि इस मुद्दे पर भाजपा की इतनी थू-थू हो चुकी है, बावजूद इसके वह चुनाव से पहले इस मरे हुये मुद्दे को बाहर कर देती है। जेडीयू प्रवक्ता और पूर्व सांसद के. सी. त्यागी ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि एनडीए में भाजपा के राम मंदिर, धारा 370 और यूनीफार्म सिविल कोड का प्रवेश वर्जित है। यदि राम मंदिर को भाजपा एनडीए के नेशनल एजेन्डे में लाने की कोशिश करेगी तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं पंजाब के उपमुख्यमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि राम मंदिर भाजपा का अपना एजेन्डा हो सकता है, वह एनडीए का एजेन्डा नहीं हो सकता है।

भाजपा के पीएम इन वेटिंग लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर के मुद्दे को फिर से उछालने के पक्ष में नहीं थे। वे इस बात से परिचित हैं कि यदि पार्टी इस मुद्दे पर ज्यादा आग्रह करेगी तो एनडीए के सहयोगी भड़क उठेंगे। बावजूद इसके राम मंदिर मुद्दे को अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नागपुर की राष्ट्रीय परिषद में जोर शोर से उठाया। दबाव में आडवाणी को भी मुद्दे पर सावधानी से मुहर लगानी पड़ी। पार्टी में इस मुद्दे को लेकर भी अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। एनडीए घटक दलों के दबाव में पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पार्टी का संकल्प है, चुनावी एजेन्डा नहीं। उन्होंने यह कहने में भी गुरेज नहीं किया कि पार्टी इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेगी।

वहीं दूसरी ओर घोषणा पत्र निर्माण करने वाली कमेटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी के करीबी सूत्रों ने बताया कि घोषणा पत्र में राम जन्म भूमि और रामसेतु दोनों ही मुद्दों को उनके महत्व के अनुसार स्थान दिया जायेगा। सूत्रों ने खुलासा किया कि इस मसले पर जोशी से वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा कर मुद्दे को चलताऊ ढंग से रखने की बात कही थी। लेकिन जोशी इस पर नहीं माने और उन्होंने घोषणा पत्र में मुद्दे के महत्व के अनुसार उसे स्थान देने के लिये दबाव बनाया। याद रहे कि राम जन्म भूमि से लेकर रामसेतु मुद्दे पर जोशी संसद से लेकर प्रधानमंत्री को समय-समय पर पत्र लिखते रहे हैं।

अयोध्या मामले में आडवाणी को राहत

नई दिल्ली (वि.सं.)। भाजपा नेता लालकृष्ण आडावाणी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रायल अलग करने के निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार दिया।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में उठाया जाना चाहिए, आपराधिक मामले में निचली अदालतों का सुपरवाईजरी कोर्ट हाईकोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केजी बालाकृष्णन, पी सथाशिवम और जेएम पांचल की पीठ के इस रुख पर अधिवक्ता वजाहत अंसारी ने याचिका वापस ले ली जिसे कोर्ट ने खाजिर कर दिया।

रामलला के दर्शनार्थियों की परेशानी पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली (वि.सं.)। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में विवादित स्थल पर रामलला के दर्शनाथियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हो रही परेशानी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी ने अर्जी दायर कर श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी का मामला उठाया था।

प्रेट्र

पुणे में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भीमसेन जोशी को भारत रत्न सम्मान दिया गया।

भीमसेन जोशी को भारत रत्न सौंपा

नई दिल्ली (वार्ता)। पंडित भीमसेन जोशी को मंगलवार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया गया। पंडित जी की अस्वस्थता के मद्देनजर यह सम्मान पुणे स्थित उनके निवास पर दिया गया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की ओर से पंडित जी को यह प्रतिष्ठित सम्मान गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ने प्रदान किया। पंडित जी को संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न से विभूषित करने के निर्णय के बाद सरकार ने उनसे जानना चाहा कि वह ये सम्मान कहां स्वीकार करना चाहेंगे। सरकार को बताया गया कि अस्वस्थ चल रहे पंडित जी के लिए दिल्ली आ पाना मुश्किल होगा। पंडित जी ने भी इच्छा जाहिर की कि वह पुणे स्थित अपने आवास पर सामान्य से समारोह में यह सम्मान प्राप्त करना चाहेंगे।

एमआईओटी में 'की-होल' सर्जरी

नई दिल्ली। एमआईओटी हॉस्पिटल्स उन चंद अस्पतालों में हैं जहां सर्जरी के लिए 'की-होल' प्रणाली का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए एमआईओटी हॉस्पिटल्स की चेयरपर्सन मल्लिका मोहनदास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 'की-होल' पद्धति लेप्रोस्कोपी व इंडोस्कोपी तकनीक पर आधारित है। उनके मुताबिक, दरअसल सर्जरी के दौरान चीरफाड़, दर्द, टांके, लंबे समय तक बेड पर पड़े रहना और ऑपरेशन बिगड़ने के खतरे इत्यादि चिंताओं के कारण अक्सर मरीज सर्जन के पास जाने से घबराते हैं।

यही वजह है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने 'की-होल सर्जरी' का विकास किया है जिसमें एक छोटे से छिद्र के जरिए सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। एमआईओटी हॉस्पिटल देश में अपनी खास पहचान के लिए जाना जाता है।

अस्पताल के पास देश-विदेश के दक्ष डॉक्टरों की टीम है जो अपने-अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। **(स.डे.)**

एमआईओटी हॉस्पिटल्स की चेयरपर्सन मल्लिका मोहनदास

पंजाब में 'सरकारी आतंकवाद' : कांग्रेस

जयशंकर गुप्त नई दिल्ली

एक-दूसरे के खिलाफ लडने के लिए मशहूर कांग्रेस नेताओं में चुनाव से पहले गजब की एकजुटता

पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर कांग्रेस के नेताओं ने यहां गजब की एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को यहां एक मंच और एक स्वर से कहा कि पंजाब में एक नए किस्म का 'सरकारी आतंकवाद' है। इस 'सरकारी आतंकवाद' के तहत राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव हो पाने पर संदेह व्यक्त करते हुए इन नेताओं ने कहा कि पंजाब में लोकसभा चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बलों की देख रेख में ही कराए जाने चाहिए।

अकाली भाजपा गठबंधन सरकार की ज्यादतियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की तस्वीरों और अन्य कागजी सबूतों के साथ यहां प्रेस क्लब में मुखातिब हए पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कोंग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष कैप्टेन अमरिंदर सिंह, विधानसभा में विपक्ष की नेता राजिंदर कौर भट्टल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह केपी, केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पुलिस अकाली नेताओं और खासतौर से नए उप मुख्यमंत्री-गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। श्री सिंह ने कहा कि हाल के स्थानीय चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी का साथ देनेवाले लोगों को गिन गिन कर तरह तरह के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्हें मारा पीटा जा रहा है। उन्होंने पुलिस और अकाली नेताओं-कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न के शिकार कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की तस्वीरों के बंडल भी दिखाए।

श्री सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब में हाल के दिनों में पांच हजार कांग्रेसजनों के खिलाफ 1100 एफआइआर दर्ज किए गए हैं।

कसाब की जान को अंडरवर्ल्ड से खतरा

मुंबई (वि.सं.)। मुंबई पर आतंकवादी हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब की जान को खतरा देखते हुए उसे भायखला स्थित महिलाओं के जेल में डाला जा सकता है। एक खबरिया चैनल के अनुसार खुफिया एजेंसी रॉ को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कसाब की जान लेने की साजिश रच रही है। रॉ के अनुसार आईएसआई ने डॉन दाऊद इब्राहिम को कसाब को मारने की सुपारी दी है और दाऊद ने यह काम छोटा शकील को दिया है। उसने 15 शार्प शूटर इस कार्य के लिए लगाए हैं। कसाब की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। उस पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा कारणों से ही कसाब को अब तक सुनवाई के लिए अदालत नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि मजिस्ट्रेट ही अपराध शाखा कार्यालय में आते हैं।

जांच की शर्त में भारत चाहता है ढील

सुशील शर्मा बेंगलूरू

मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री के विमान की भी अमेरिका में हो सकती है जांच

मौजूदा अमेरिकी कानूनों के तहत अमेरिका चाहे तो भारत के विशिष्ट व्यक्तियों के लिए बेचे गए अपने तीन बोइंग बिजनेस जेट विमानों की सालाना जांच कर सकता है यानी भारत के प्रधानमंत्री के विमान की भी फिजिकल जांच की जा सकती है। ऐसा एंड यूजर मॉनिटरिंग शर्त के कारण है। इस पर ऐतराज के बावजूद भारत इन्हीं कानूनों के तहत अमेरिका से कई सामग्री खरीदने को मजबूर रहा है।

भारत की आपत्तियों तथा भारत को हथियार बेचने की बड़ी मंडी समझते हुए भारत को उम्मीद है कि अमेरिका कानून की भाषा में कुछ ढील देने को तैयार हो जाए लेकिन अमेरिका ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। भारत ने अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स कानून में बदलाव के लिए एक मसौदा तैयार किया है जिसे एक सप्ताह में अमेरिका के सामने रखा जाएगा। गत नवंबर में रक्षा मंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उनकी एफएमएस या लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर अमेरिका से कोई बात हुई। एयरोइंडिया में भाग लेने आए अमेरिकी डिफेंस सिक्यूरिटी कॉआपरेशन एजेंसी के निदेशक वाइस एडमिरल जेफ्रे ए. वेरिंगा ने कहा कि एंटनी की इस बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात हुई थी और एंटनी का रवैया सकारात्मक था। उस बैठक में स्वयं वेरिंगा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि भारत ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के लिए भाषा में बदलाव करते हुए एक मसौदा तैयार किया है जिसे एक सप्ताह में अमेरिका को विचार के लिए दे दिया जाएगा। उन्होंने यह गारंटी नहीं दी कि अमेरिका इस मसौदे को स्वीकार कर ही लेगा पर 10 अरब डालर के लड़ाकू विमानों के सौदे की उम्मीद में संभव है वह इसे स्वीकार कर ले।

कुछ सेक्टरों में हवाई यात्रा हुई महंगी

नई दिल्ली। कम किराए वाली उड़ान उपलब्ध कराने वाली कंपनियों सहित विभिन्न विमानन कंपनियों ने कई सेक्टरों के किराए में छूट के आकर्षक प्रस्ताव वापस लेते हुए मंगलवार से बेसिक किराए में लगभग 2,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी कर दी।

सूत्रों के अनुसार यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कई मार्गों पर बेहद लुभावने बेसिक किराए का प्रस्ताव रखे जाने के बावजूद यात्रियों ने इसमें बहुत रुचि नहीं दिखाई।

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमने कम किराए वाले आकर्षक प्रस्ताव वापस ले लिए क्योंकि लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जो लोग इन योजनाओं के तहत टिकट ले चुके हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।' निजी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रवक्ता ने भी कहा कि कंपनी ने अब कम किराए संबंधी योजनाएं समाप्त कर दी हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अब सीट की बुकिंग के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

(आईएएनएस)

शिलान्यास के बहाने चुनावी शंखनाद

डेहरी ऑन सोन में मंगलवार को सोनिया गांधी ने पूर्वी फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। साथ में लालू यादव भी हैं। प्रेट्र

आलोक चन्द्र डेहरी

पूर्वी फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण का शुभारंभ करने के बाद एक सभा में सोनिया गांधी ने पांच वर्ष की यूपीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं लालू प्रसाद ने रेलवे को बिहार के विकास का द्वार बताया। श्रीमती गांधी ने कहा कि पांच वर्षों के बाद यूपीए अपने काम को लेकर जनता के बीच आया है। श्री प्रसाद ने कहा कि रेलवे सूबे की तरक्की का कारण बनेगा और रोजगार के इतने अवसर पैदा करेगा जिससे अन्य राज्य के लोग भी बिहार का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने हर रेल कारखाने के साथ एप्रेन्टिस स्कूल खोलने और उसके प्रशिक्षित लोगों को कारखाने में रोजगार देने की घोषणा की।